RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : सोमवार, 31 अक्टूबर 2022 वर्ष 04 अंक 167 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र को लगा करोड़ों का फटका...!

आदित्य के बयान से शिंदे को झटका

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र 22,000 करोड़ रुपये के टाटा एयरबसः प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच एक नया आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है. इस प्रोजेक्ट को गंवाने से क्या एकनाथ शिंदे की चुनावी रणनीतियों पर फर्क पड़ सकता है... दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में महाराष्ट्र कितना पीछे हो जाएगा ? राज्य में बड़े निवेश राज्य के हाथ से बाहर निकलने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. हालांकि कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र को प्रस्तावित किया गया था और राज्य अग्रणी प्रतिद्वंदी भी था. इससे कई सवाल खड़े हुए हैं

नवी मुंबई में पेड़ों के लिए होगी 9 नवंबर से सुनवाई!

... नवी मुंबई महानगरपालिकाने जारी किया नोटिस!

नवी मुंबई : वाशी स्थित महात्मा फुले जंक्शन से कोपरी जंक्शन तक उड़ान पुल बनने की तैयारी नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा की गई है, लेकिन इस पुल के निर्माण में 390 पेड़ बांधा बने हुए हैं, इनमें से 6 पेड़ों को काटने और 384 पेड़ों को स्थानांतरित करने की योजना महानगरपालिका द्वारा बनाई गई है। उक्त उड़ान पुल से प्रभावित होने वाले पेड़ों की कटाई को लेकर महानगरपालिका ने 9 नवंबर 2022 से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण ने पेड़ों को लेकर आपत्ति दर्ज कराने वाले संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर हाजिर होने को कहा है।

गौरतलब है कि ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका 361 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा फुले जंक्शन से कोपरी जंक्शन तक उड़ान पुल बनाने जा रहा है। इस पुल के लिए 6 पेड़ काटे जाएंगे और 384 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। इस पुल से 384 पेड़ प्रभावित होंगे, जिसे महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण ने उनके पुनर्रोपण के लिए नागरिकों से सुझाव और आपत्ति मांगी थी। जिस पर 9 नवंबर से सुनवाई होगी। कहा जाता है कि इस उड़ान पुल का जल्द से जल्द निर्माण के लिए मंत्रालय की ओर से महानगरपालिका पर दबाव है। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के चलते उक्त मुद्दा ठंडा पड़ गया था, लेकिन नई सरकार के स्थिर होने के बाद फिर से यह मुद्दा गरमा रहा है।

बड़ी संख्या में दी गई हैं सुझाव और आपत्तियां

गौरतलब है कि उक्त पेड़ की कटाई को रोकने के लिए नवी मुंबई के लोगों ने महानगरपालिका को बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां दी हैं। उक्त पेड़ों के संरक्षण के पर्यावरणविदों और कुछ सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई है और इसकी शिकायत राज्य के पर्यावरण विभाग से की है। इस संबंध में ऐरोली के विधायक गणेश नाईक ने पेड़ों को बचाने के लिए उड़ान पुल के निर्माण का सख्त विरोध किया है। इस पृष्ठभूमि में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महानगरपालिका का वृक्ष प्राधिकरण इस मामले में नवी मुंबईकरों की भावनाओं का कितना सम्मान करता है।

सोरातिया मुस्लिम घाची जमात के मुंबई चुनाव माहिम में तनावपूर्ण

बिना पुलिस की इजाजत के चुनाव रखा गया

मुंबई : सोरातिया मुस्लिम घाची जमात के मुंबई चुनाव माहिम में तनावपूर्ण दिन भर लड़ाई झगडे मारामारी होती रही । खास बात यह है कि बिना पुलिस की इजाजत के चुनाव रखा गया, जिसमें मुंबई भर से सोरातिया मुस्लिम घाची जमात के हजारों लोग अपना वोट डालने माहिम आने वाले थे ।

चुनाव खुद जमात कराने की योजना बनाई थी लेकिंन इसमे हेराफेरी ऐसी घटना हुई ऐसा आरोप खुद जमात के वोटरों ने लगाए। इसके चलते माहौल खराब हुआ। इसका असर माहिम में देखने मिला । जमात के लोग रोड पर उतरकर आपस मे भी भिड़े । इतवार का दिन होने से दरगाह में श्रद्धालुओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा । माहिम दरगाह के सामने का रोड पूरी तरह लोगो की गरधी हुई और भगदड़ हो सकती थी। अगर पुलिस समय रहते लोगो को तीतर बितर नही करती । माहिम पुलिस स्टेशन के अधिकारी से जब संपर्क किया गया, तो उनका कहना था कि बिना इजाजत के चुनाव रखा गया और कोई सरकारी महकमे की भागीदारी नही थी । अधिकारी ने कहा- अपराधियों के खिलाफ दर्ज होंगे मामले ।

गोराई चारकोप में लिफ्ट में फंसकर महिला की मौत!

मुंबई : गोराई चारकोप में इमारत की लिफ्ट में फंसकर एक 62 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। गोराई चारकोप स्थित हाईलैंड्स ब्रिज इमारत के चौथे मंजिल पर नगीना अशोक मिश्रा फंस गई थी, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के लिए एक बार लिफ्ट का मुद्दा गरमाया गया है।

यह हादसा 21 अक्टूबर का है। नगीना अशोक मिश्रा हाईलैंड्स ब्रिज इमारत के चौथे मंजिल पर रहती हैं। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिफ्ट में घुसी, लेकिन लिफ्ट चौथे और तीसरे महले के बीच अचानक रुक गई। नगीना मिश्रा ने घबराकर अपने बेटे को पुकारा। दरवाजा खोलते समय बिजली का शॉक लगने के बाद सीढ़ियों से भाग कर लाइट बंद किया। इसके बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। इससे लिफ्ट के फर्श में दो बड़े होल हो गए। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया कुछ दिन चले उपचार के बाद महिला की मौत हो गई। पिछले दो महीने में लिफ्ट हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। मालाड के चिंचोली बंदर में 17 सितंबर को एक 26 साल की शिक्षिका की फंस कर मौत हो गई थी। इसी तरह कांदिवली में एक 70 वर्ष के बुजुर्ग की लिफ्ट में अटकने से मौत हो गई थी।

अमरावती में बिल्डिंग ढहने से 5 की मौत

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की मुआवजे की घोषणा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के अमरावती में एक जर्जर इमारत के गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. घटना अमरावती के प्रभात टॉकीज सिनेमा क्षेत्र में हुई. अधिकारियों ने कहा, 'दो मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई. इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी.' घालय शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बचाव और राहत कार्य हो पूरा कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है.

इससे पहले जून में मुंबई के कुर्ला में चार मंजिला इमारत गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्ला इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों

के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की. इससे पहले, शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुडलकर ने घटना में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और घोषणा की कि मृतक के परिवार को प्रत्येक को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि घायलों को एक लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े ने कहा कि ढह गई इमारत जीर्ण-शीर्ण थी, 2013 से पहले इसकी मरम्मत के लिए नोटिस दिए गए थे, और फिर इसके विध्वंस के लिए.

मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी कुर्ला का दौरा किया और कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस पर ऐसी संपत्ति खाली कर दी जानी चाहिए थी. ठाकरे ने कहा, 'जब भी बीएमसी नोटिस जारी करे, (इमारतें) खुद खाली कर देनी चाहिए..अन्यथा, ऐसी घटनाएं होती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं. अब इस पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है.'

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

पारदर्शिता की दिशा में...

दुनिया में बड़े डिजिटल प्लेटफ़ार्म वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी गूगल पर एक हफ्ते के भीतर दो बार बड़ा जुमार्ना लगाकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने चेताया है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भारत में मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। साथ ही यह भी कि उसे भारतीय हितों की अनदेखी की इजाजत नहीं दी जा सकती। उम्मीद की जानी चाहिए कि दो चरणों में दो हजार दो सौ करोड़ के भारी-भरकम जुमार्ने के बाद कंपनी के निरंकुश व्यवहार में कमी आयेगी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित तौर-तरीके अपनाने के प्रति गूगल को चेताया भी है। दरअसल, गूगल अपने एप डाउनलोड करने वाले प्ले स्टोर के वर्चस्व का लाभ उठाकर तमाम एप डेवेलपर्स पर दबाव डालती रही है कि वे अपने एप से संबंधित सभी भुगतान गूगल के भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के जरिये ही करें। इसको लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग ने चेतावनी दी है कि एप डेवेलपर्स को अपने पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म का ही प्रयोग करने को बाध्य न करे। दरअसल, इससे पहले सीसीआई ने एंड्रॉयड मामले में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने का आरोप गूगल पर लगाया था। आरोप था कि गूगल स्मार्टफ़ोन निमार्ताओं को बाध्य करती रही है कि वे प्रत्येक फ़ोन में गूगल एप्स को अनिवार्य रूप से शामिल करें, तभी उन्हें एंड्रॉयड तकनीक के प्रयोग की इजाजत मिलेगी। गूगल की इस हरकत को सीसीआई ने बाजार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा कानून का अतिक्रमण बताया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल पर अन्य मामलों में सीमाएं लांघने पर जुमार्ना लगा चुका है। दरअसल, पूरी दुनिया में गूगल अपने वर्चस्व के चलते अनैतिक कारोबार का सहारा ले रहा है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया समेत कई देश गूगल पर जुमार्ना लगा चुके हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर गूगल के वर्चस्व को तोड़ने के लिये दुनिया के तमाम देश विकल्प तलाशने की जुगत में लगे हैं। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य मामलों में भी गूगल की अनियमितताओं की निगरानी कर रहा है।

विगत में भी विदेशों व भारत में मीडिया संस्थान नियमों का उल्लंघन करके समाचारों से मुनाफा कमाने के आरोप गूगल पर लगते रहे हैं। बाकायदा आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों ने इस बाबत जुमार्ना भी वसूला है। बहरहाल, सीसीआई द्वारा गूगल पर लगाया गया जुमार्ना साफ संदेश है कि वह अनुचित व्यावसायिक परिपाटियों से परहेज करे। भारत में हालिया जुमार्ने उसे अमेरिकी तकनीकी दिग्गज एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस को लेकर अपने दबदबे का दुरुपयोग व एप डेवेलपर्स को भारत में तीसरे पक्ष की बिलिंग भुगतान सेवाओं को बाधित न करने के निर्देश के रूप में लगाये गये हैं। इस कार्रवाई के बाद गूगल प्रबंधन बचाव की मुद्रा में है और दलील दे रहा है कि वह इन सेवाओं के उपयोगकर्ताओं तथा डेवेलपर्स को बेहतर सेवाएं देने के लिये प्रतिबद्ध है। साथ ही यह कि उसने भारतीय मॉडल में कम लागत रखते हुए डिजिटल मुहिम में योगदान दिया है। सीसीआई की कार्रवाई का मकसद यही है कि डिजिटल डोमेन में स्वस्थ स्पर्धा का विकास हो। साथ ही बड़े खिलाड़ियों को इस बाजार में एकाधिकार करने से रोका जा सके। निस्संदेह, भारत में गूगल के लिये बड़ा बाजार है, जिसे वह गंवाना नहीं चाहेगा। उल्लेखनीय है कि देश के साठ करोड़ स्मार्टफ़ोन में से 97 फीसदी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से संचालित हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुंबईकरों पर मंहगाई की मार...

जून, 2022 से बीएमसी ने बढ़ाए पानी के दाम, 7.12 प्रतिशत की हुई वृद्धि!

मुंबई: महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों का अब पानी भी महंगा हो जाएगा। बीएमसी ने पानी की दर में 7.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। योजना के अनुसार, नई दर जून, 2022 से लागू होगी। बीएमसी की दर वृद्धि का असर स्लम से लेकर फाइव स्टार हॉटेल तक पड़ेगा। पानी की दर में 35 पैसे से लेकर 6.35 रुपये तक की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है, इसे कमिश्नर के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। बता दें कि 2021 में बीएमसी ने पानी की दर में 5.29 प्रतिशत की वृद्धि की थी। बीएमसी प्रशासन के इस फैसले का कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध किया है। बीएमसी जलापूर्ति विभाग के एक

अधिकारी ने बताया कि 2012 में यह नियम बनाया गया था कि हर साल पानी की दर में अधिकतम 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी। झोपड़पट्टी में अभी पानी की दर 4.93 रुपये है, जो बढ़कर 5.28 रुपये हो जाएगी। यह दर प्रति 1000 लीटर पानी पर लागू होगी। इसी तरह बीएमसी इमारतों को मौजूदा समय में पानी 5.94 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से उपलब्ध कराती है, जो बढ़कर 6.36 रुपये हो जाएगी। नॉन कमर्शियल जगहों पर पानी की दर में भी 1.49 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कमर्शियल जगहों में पानी के लिए अब लोगों को 47.65 रुपये देने पड़ेंगे। मुंबई में उद्योग-कारखाना चलाने वालों को अब प्रति हजार लीटर पानी के लिए 63.65 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पॉश रेसकोर्स, थ्री-फाइव स्टार हॉटेलों से बीएमसी अब तक एक हजार लीटर के बदले 89.14 रुपये लेती है, जो अब बढ़कर 95.49 रुपये हो जाएगा।

बीएमसी अधिकारी का कहना है कि मुंबईकरों को प्रतिदिन 3850 एमएलडी पानी की आपूर्ति सातों झीलों से की जाती है। जिस कीमत पर लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, वह बहुत ही मामूली दर है, जबकि बीएमसी कई गुना खर्च करती है। बीएमसी प्रशासन ने पानी आपूर्ति पर होने वाले खर्च को भी गिनाया है। जो काम 518 रुपये में होता था, वह अब 577 रुपये हो गया है। पानी आपूर्ति के लिए प्रशासनिक खर्च 125 रुपये से घटकर 85 रुपया हो गया है, लेकिन ऊर्जा खर्च 221 रुपये से बढ़कर 222 रुपया हो गया है।

बहन के साथ छेड़खानी का नाबालिग ने किया विरोध, चाकू मारकर हत्या!

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात...

दिल्ली : दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में एक 17 वर्षीय किशोर की दो अन्य नाबालिगों ने मिलकर हत्या कर दी. हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है. दरअसल 17 वर्षीय मनोज की आरोपियों ने इस वजह से हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था. हत्या की इस पूरी वारदात का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था. सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दोनों आरोपियों ने मिलकर मनोज की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के विरोध के दौरान मनोज ने एक नाबालिग आरोपी को थप्पड़ भी जड़ दिया था. बस इसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोनों नाबालिग लड़कों ने शुक्रवार (28 अक्टूबर) को मनोज के घर के पास ही उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी. मनोज उस समय कंप्यूटर ट्यूशन पढ़कर वापस आ रहा था. सीसीटीवी में कैद इस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक लड़का मनोज पर चाकू से हमला कर रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि मनोज किस तरह से हमले के दौरान खुद को उस लड़के के वार से बचने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय एक और किशोर चाकू लेकर मनोज पर हमला कर देता है और दोनों मिलकर मनोज की हत्या कर देते हैं. मनोज के परिजनों ने बताया कि वो आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था. इलाके के ही रहने वाले कुछ लड़के मनोज की बहन के साथ आए दिन छेड़खानी किया करते थे. बस इसी बात को लेकर मनोज का उन लड़कों से झगड़ा भी हुआ था.

फिंगर प्रिंट के क्लोन से लाखों रुपये उड़ाने वाले गैंग का पदार्फाश...!

ई-श्रम कार्ड अपडेट कराने के बहाने लोगों से लेते थे उंगलियों के निशान

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ में फिंगरप्रिंट के क्लोन और आधार कार्ड से रुपये निकालने वाले जालसाजों का पदार्फाश हो गया है। आरोपी आरोपी ई-श्रम कार्ड अपडेट करवाने के बाहने गांव-गांव जाकर लोगों के उंगलियों के निशान इकट्ठा करते थे। पुलिस ने गिरोह के तीन युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। युवकों के पास से कंप्यूटर उपकरण, फिंगर प्रिंट डिवाइस बरामद हुआ है।

ये मामला हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है। हाल ही में पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से बैंक अकाउंट से रुपये निकाले जा रहे हैं। जब ये ये मामला आला अफसरों तक पहुंचा तो इसकी जांच शुरू हो गई। इस दौरान पता चला कि कुछ महीने पहले ई-श्रम कार्ड बनाने का काम बड़े स्तर पर हुआ था, जिसमें लोगों से उनके फिंगर प्रिंट के निशान लिए गए थे। इसी को जालसाजों ने ठगी का आधार बनाया। थाना प्रभारी केपी सिंह राठौर के मुताबिक जांच के दौरान जनसेवा केंद्र चलाने वाले भीमनगर के गणेश का नाम सामने आया। पुलिस

ने जब हिरासत में लेकर गणेश से पूछताछ कि तो उसने सारी बात बता दी। गणेश ने बताया कि प्रभातनगर में वह जनसेवा केंद्र चलाता है। जहां फिंगर प्रिंट और आधार कार्ड से रुपये निकालने की व्यवस्था है। हाल ही में उसकी मुलाकात मोहनलाल से हुई। वह फिंगर प्रिंट से क्लोन तैयार करने में माहिर है। जिसके बाद उन्होंने एक अन्य जनसेवा केंद्र संचालक हरि ओम कश्यप को अपने साथ मिला लिया। गणेश ने पुलिस को बताया कि तीनों ने ई-श्रम कार्ड अपडेट कराने के बहाने गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किया। फिर सबके फिंगर प्रिंट जुटाने लगे। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक-एक करके लोगों के बैंक अकाउंट से रुपये निकालने लगे। मोहनलाल के बताया कि इंटरनेट लिंक के माध्यम फिंगर प्रिंट क्लोन तैयार करता था। क्लोन का फिंगर प्रिंट स्कैनर का प्रयोग करके अपने काम को अंजाम देते थे।

ऊर्जा क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की मोदी सरकार की तैयारी...!

मुंबई : केंद्र की सत्ता पर काबिज पीएम नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की मंशा पूरे देश पर एकछत्र राज करने की है। देश के सभी राज्यों में भी भाजपा पावर में हो, ऐसा प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। धनतेरस पर 'प्रसारण बंदी' का पटाखा फोड़ने अर्थात राज्यों से प्रसारण के अधिकार पर सेंसरशिप लगाने के बाद अब केंद्र सरकार राज्यों का 'फ्यूज' यानी 'ऊर्जा' मामलों का नियंत्रण भी पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहती है। ऐसा इसलिए ताकि राज्य ऊर्जा के मामले में भी पूरी तरह केंद्र पर ही निर्भर रहें।

ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर करने तथा बिजली कंपनियों के निजीकरण का आरोप तो केंद्र सरकार पर पहले ही लगता रहा है। अब प्रस्तावित 'विद्युत संशोधन विधेयक २०२२' को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस आशय के अधिनियम से ऊर्जा क्षेत्र के कामकाज में बाधाएं आएंगी व केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र और मजबूत होगा।

कोयले की कमी व अन्य संसाधनों की वजह से ऊर्जा क्षेत्र पहले से ही हिचकोले खा रहा है। कई बिजली कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं। बिजली उत्पादन और मांग की आपूर्ति को लेकर देशभर में बवाल मचा रहता है। बिजली कंपनियां तरह-तरह के कारण बताकर बिजली बिल की दर में बढ़ोतरी करती रही हैं। बिजली कंपनियां मनमानी न कर सकें और ग्राहकों का हित बरकरार रहे इसलिए विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। अब नियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र पर भी ग्रहण मंडराने लगा है। बिजली क्षेत्र में अब केंद्र सरकार अपना दबदबा बनानी चाहती

है, इसलिए प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक २०२२ को पारित कराने की तैयारी में है। इस विधेयक को लेकर विद्युत नियामक आयोगों (ईआरसी) के संयुक्त शीर्ष निकाय 'फोरम ऑफ रेगुलेटर्स' (फॉर) ने आपत्ति जताई है। विद्युत अधिनियम २००३ का एक ध्येय यह कि शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया से सरकार को दूर किया जाए। इसलिए नियामकीय आयोग का गठन सुनिश्चित हुआ था। इस क्रम में केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक गठित किए गए थे। 'फॉर' ने विभिन्न धाराओं के लिए की गई सिलसिलेवार टिप्पणी में कहा है कि नियामक को कानून बनाने चाहिए। यह कार्य केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके मुताबिक कुछ धाराओं के जरिए ऊर्जा के वितरकों के लिए रास्ता खोला गया है, ताकि वे निजी निवेश कर सकें। ये धाराएं विवादों के समाधान के तरीके और दंड के प्रावधानों से भी संबंधित हैं। दस्तावेज के मुताबिक हाल में विद्युत अधिनियम २००३ में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को अधिक शक्तियां दे दी गई हैं।

'फॉर' के अनुसार हिंदुस्थान के संविधान की समवर्ती सूची में विद्युत आता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों पर इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। इस लिहाज से विद्युत अधिनियम २००३ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को लेकर बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित किया गया था। हालांकि इस अधिनियम में कई प्रस्तावित संशोधन सामंजस्य का झुकाव केंद्र सरकार की ओर कर देंगे। 'फॉर' की यह राय ऊर्जा की स्थायी समिति को सुपुर्द कर दी गई है। फिलहाल, ऊर्जा की स्थायी समिति विद्युत विधेयक २०२२ पर साझेदारों के साथ चर्चा कर रही है। 'फॉर' ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि इस प्रस्तावित विधेयक में विद्युत विधेयक के मूल आधार को खत्म किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में कई नियामकीय गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया है। इससे इस क्षेत्र में भ्रम की अपरिहार्य स्थिति पैदा हो सकती है। ऊर्जा क्षेत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए इन संशोधनों से बचना चाहिए।

पूर्व मेयर को दादर पुलिस का समन, एसआरए फ्लैट स्कैम मामले में एक्शन!

मुंबई : एसआरए फ्लैट स्कैम मामले में शिवसेना नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में अब दादर पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। किशोरी पेडनेकर को 31 अक्तूबर को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

पिछली तारीख पर पेश नहीं हुई थीं शिवसेना नेता

बता दें कि किशोरी पेडनेकर को इससे पहले 29 अक्तूबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुईं। ऐसे में दादर पुलिस ने उन्हें 31 अक्तूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

मुंबई की अदालतों में 10 साल पुराने मामलों में ट्रायल शुरू होना बाकी...

मालेगांव ब्लास्ट का भी यही हाल

मुंबई : मुंबई की अदालतों में 10 साल से अधिक पुराने मामले पड़े हुए हैं, जिसमें अभी तक सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है। इन मामलों में आरोपियों ने सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। सालों से जेल में बंद कुछ आरोपियों बताया भी कहा है कि उन्हें दोषी ठहरा दिया जाए।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (वअढअ) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नामित मुंबई में दो विशेष अदालतों ने कहा है कि उनके ऊपर ह्लअत्यधिक बोझह्व है। 2011 में मुंबई ट्रिपल धमाकों से संबंधित एक मामले में न केवल आरोपी ने बल्कि यहां तक कि जांच एजेंसी (महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते) ने भी अगस्त में एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुकदमे में रोज सुनवाई की मांग की गई। बता दें कि इस मामले में 11 आरोपियों को आतंकी हमलों के 11 साल बाद भी सुनवाई शुरू होना बाकी है। 13 जुलाई 2011 को दादर, जावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में हुए तीन सिलसिलेवार धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष ने 700 से अधिक गवाहों को प्रस्तुत किया है। 2019 से 2021 के दौरान अलग-अलग कार्यवाही में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे लेकिन मुकदमा शुरू होना बाकी है।

एटीएस और आरोपी नदीम अख्तर दोनों ने मामले में दैनिक सुनवाई की मांग की है, जिसपर न्यायाधीश ने कहा कि उनके पहले के न्यायाधीश ने इसी तरह की याचिका पर एक आदेश पारित किया था कि एक अदालत के रूप में प्रतिदिन सुनवाई करना मुश्किल है। अदालत ने नदीम अख्तर की यह कहते हुए खिंचाई की कि वह मामले की हर तारीख पर आवेदन दाखिल कर रहा और उसका कोई छिपा हुआ इरादा है। कोर्ट ने एटीएस की याचिका को भी खारिज कर दिया। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी हारून नाइक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि मुकदमे को तेजी से समाप्त करने का निर्देश देते हुए उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत थे।

विदेशी मुद्रा भंडार २ साल के निचले स्तर पर!

मुंबई : देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। मोदी राज जब से आया है, उसने देश की अर्थव्यवस्था को ठगा ही है। दूसरी तरफ रुपए के बाद अब फॉरेक्स भी दगा दे रहा है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने डेटा जारी करके बताया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार २ साल से ज्यादा के निचले स्तर तक चला गया है। देश की करेंसी रुपए की गिरावट इसकी बड़ी वजह भी है और फॉरेन करेंसी ऐसेट्स भी घटे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार २१ अक्टूबर को खत्म हफ्ते में ३.८५ अरब डॉलर घटकर ५२४.५२ अरब डॉलर पर आ गया है। आरबीआई ने डेटा जारी करके बताया है कि रुपए की लगातार गिरावट को थामने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी जा रही है।

स्पॉट फॉरेक्स रिजर्व जो पिछले साल सितंबर में ६४२.४५ अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, पर अब इसमें ११७.९३ अरब डॉलर की कमी आ गई है। इतनी भारी गिरावट इस बात का इशारा कर रही है कि आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक नहीं है।

हिंदुस्थान के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट का कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। इसे थामने के लिए आरबीआई को अपने खजाने से और डॉलर की बिकवाली करनी पड़ सकती है। इसके चलते फॉरेक्स रिजर्व और घटेगा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के पीछे वजह ये भी है कि यहां फॉरेन करेंसी ऐसेट्स तेजी से घट रहे हैं और इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर देखा जा रहा है। चिंता करनेवाली बात ये भी है कि पिछले १२ में से ११ हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट ही दर्ज की गई है और ये आंकड़ा देश के खजाने की विकट स्थिति को बढ़ा सकता है। फॉरेन करेंसी ऐसेट्स और गोल्ड रिजर्व के आंकड़े जानिए। फॉरेन करेंसी ऐसेट्स को देखें तो २१ अक्टूबर को खत्म हफ्ते में ये ३.५९ अरब डॉलर से घटकर ४६५.०८ अरब डॉलर पर आ गए हैं। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व २४७ लाख डॉलर से घटकर ३७.२१ लाख डॉलर पर आ गया है। त्योहार के मौसम में नकदी की बढ़ी मांग, कर वसूली बढ़ने और मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप से कुल मिलाकर बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी करीब खत्म हो गई है। पिछले ५ दिन में रिजर्व बैंक ने रोजाना बैंकिंग व्यवस्था में औसतन ७२,००० करोड़ रुपए डाले हैं। समीक्षाधीन सप्ताह में रुपया डॉलर के मुकाबले रेकॉर्ड गिरावट स्तर ८३.२९ पर पहुंच गया था। आरबीआई को इस गिरते रुपए को संभालने के लिए डॉलर बेचना पड़ता है। पिछले १२ में से ११ सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई है। ७ अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में इसमें उछाल आया था। स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी के चलते उस सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार २०४ मिलियन डॉलर बढ़ गया था।

साइबर सेल ने महात्मा फुले विश्वविद्यालय के छात्र को किया गिरफ्तार, लगा है बेहद गंभीर आरोप...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने महात्मा फुले विश्वविद्यालय, राहुरी के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। छात्र पर आरोप है कि उसने ट्विटर हैंडल का उपयोग करके सीएम और डिप्टी सीएम और कुछ महिला पत्रकारों सहित संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए। महाराष्ट्र साइबर सेल के एसपी संजय शित्रे ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसे 2 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया है।

विधायक बच्चू कडू ने रवि राणा से माफी मांगने को कहा...!

मुंबई : प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने निर्दलीय विधायक रवि राणा से माफी मांगने को कहा है। राणा ने कडू पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे नीत खेमे में शामिल होने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। राणा और कडू ने शिंदे-भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे का हल निकालने की मांग की है। राणा रविवार को मुंबई पहुंचे और कडू के रविवार रात तक पहुंचने की संभावना है। इस साल जून में शिंदे की अगुवाई में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत की गयी थी, जिसके कारण तत्कालीन उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिर गयी थी। कडू उस सरकार में मंत्री थे। शिंदे ने बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से सरकार बना ली। राणा और कडू अमरावती जिले में क्रमशः बदनेरा तथा अचलपुर विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा मुख्यमंत्री शिंदे नीत गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कडू ने राणा को आरोपों का सबूत पेश करने या माफी मांगने तथा उनके खिलाफ लगाए आरोप वापस लेने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही यह बताए कि गुवाहाटी गए विधायकों को पैसे दिए गए थे, या नहीं। राणा रविवार को अमरावती से मुंबई पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''शिंदे और फडणवीस मेरे नेता हैं और मुझे मुंबई बुलाया गया है इसलिए मैं आया हूं।'' कडू के भी मुंबई पहुंचने की संभावना है। उन्होंने अमरावती में कहा कि राणा के आरोपों से उनकी मानहानि हुई है तथा अगर इस मुद्दे का कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला तो उन्हें मजबूरन कोई ''बड़ा कदम'' उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि सात से आठ विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बताया। कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी के 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में दो विधायक हैं। शिंदे के पास शिवसेना के 39 बागी विधायकों के साथ ही कुछ निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायकों का समर्थन हासिल है। भाजपा के सदन में 106 विधायक हैं।

केईएम अस्पताल में रोज आते हैं ब्रेन 'स्ट्रोक' ७०-८० मरीज

मुंबई : ब्रेन 'स्ट्रोक' सामान्यतः बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती है। लेकिन इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी ने युवाओं के ब्रेन पर भी गहरा वार किया है। इन दिनों अनेक युवा ब्रेन स्ट्रोक की शिकायतें लेकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मनपा के केईएम अस्पताल में ही महीने में २४० स्ट्रोक के मरीज भर्ती हो रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि स्ट्रोक का स्ट्राइक रेट इतना खतरनाक होता है कि यह एक मिनट में ३२ हजार मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्थान गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बोझ का सामना कर रहा है। इनमें से स्ट्रोक 'सबसे' आम बीमारियों में से एक है। स्ट्रोक का मतलब ब्रेन अटैक है, जो देश में विकलांगता का एक प्रमुख कारण भी है। आयु चाहे जो हो, स्ट्रोक किसी को और कभी भी हो सकता है। वहीं बीते कुछ सालों से मुंबई जैसे शहरों में रहनेवाले लोगों की जीवनशैली में तेजी से बदलाव आया है। इस बदलाव ने खासकर युवाओं में खतरा पैदा कर दिया है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे स्ट्रोक के मामलों के लिए खुद युवा ही जिम्मेदार हैं। केईएम अस्पताल में स्ट्रोक विभाग के प्रमुख डॉ. नितिन डांगे ने कहा कि जीवन शैली और भोजन की आदतों में बदलाव के कारण देश में बीते कुछ सालों से स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। जंक फूड, तली हुई चीजें खाना, गतिहीन जीवन शैली, धूम्रपान, व्यायाम की कमी, मधुमेह मेलिटस, उच्च रक्तचाप और विकृत लिपिड प्रोफाइल आदि जैसे कारणों के कारण स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है।

मुंबई की आरे कॉलोनी में पांच दिन में दूसरी बार तेंदुआ पकड़ा गया

मुंबई : वन विभाग ने रविवार सुबह मुंबई की आरे कॉलोनी से एक नर तेंदुआ पकड़ा। पिछले पांच दिन में क्षेत्र में तेंदुआ पकड़े जाने की यह दूसरी घटना है। एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ आरे कॉलोनी की 15 यूनिट में लगाए पिंजरे में फंस गया। आरे मुंबई का हरित क्षेत्र है, जो पश्चिमी उपनगर गोरेगांव में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के पास स्थित है। उन्होंने बताया कि तेंदुए को बाद में एसजीएनपी में एक बचाव केंद्र तक ले जाया गया। इससे पहले, सोमवार सुबह आरे कॉलोनी की 15 नंबर यूनिट में एक वन्य क्षेत्र में तेंदुए ने अपने मां के पीछे मंदिर की तरफ जा रही डेढ़ साल की बच्ची पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को आरे की 17 नंबर यूनिट में एक नर तेंदुआ पकड़ा गया और उसे एसजीएनपी में एक बचाव केंद्र ले जाया गया है।

वन्य अधिकारियों को संदेह है कि यह वही तेंदुआ है, जिसके हमले में बच्ची की मौत हो गई थी। अधिकारी के मुताबिक, सोमवार को हुई घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अहम स्थानों पर तीन पिंजरे लगाए थे। उन्होंने बताया कि वन्य अधिकारी इलाके में लगाए 30 कैमरों और एक पिंजरे की मदद से अन्य तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रखते रहेंगे। अधिकारी के अनुसार, करीब 30 वन्यजीव स्वयंसेवी, गैर-सरकारी संगठन के सदस्य, वन विभाग के अधिकारी और एसएनजीपी के कर्मी इलाके में मनुष्य-पशु के बीच संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

...करेंगे शिंदे सरकार की बर्खास्तगी की मांग -कांग्रेस

मुंबई : महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के अनुसार अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल यानी आगामी सोमवार 31 अक्टूबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा और वर्तमान राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अपने तरफ से मांग करेगी। इस बाबत जानकारी आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। गौरतलब है कि, इसके पहले भी नाना पटोले ने कहा था कि दिवाली के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। पटोले ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के लिए शिंदे सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं इस बयान पर महाराष्ट्र के उट एकनाथ शिंदे ने कहा था कि, नाना पटोले का बयान बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा था कि, अन्नदाता किसान आज संकट में हैं। ऐसे में हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। उनकी मदद हम जरूर करेंगे। विपक्ष का काम है आलोचना करना और इसी लिए नाना पटोले ने आलोचना की है। उनके विरोध का जवाब हम अपने काम से देंगे।

भारती-हर्ष के खिलाफ एनसीबी ने दायर की २०० पन्नों की चार्जशीट

मुंबई : बॉलीवुड, टेलीविजन इंडस्ट्री अक्सर विवादों में घिरती रहती हैं। अभिनेताओं, अभिनेत्रियों पर बड़ी-बड़ी पार्टियों में ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे ही कॉमेडी क्वीन कही जानेवाली भारती सिंह पर भी ड्रग्स रखने का आरोप लगा था। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। कॉमेडी क्वीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ २०० पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद अब यह मामला कोर्ट में हल किया जाएगा। दरअसल दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद से ही एनसीबी ने बॉलीवुड सेलेब्स पर शिकंजा कसा है। २०२० में हुई इस जांच के दौरान कई स्टार्स के नाम भी सामने आए थे। उनमें कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष का नाम भी शामिल था। एनसीबी को कॉमेडियन के घर और ऑफिस में छापेमारी के दौरान ड्रग्स मिले थे, जिसके बाद भारती और उनके पति को ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया था।

मैं होता तो इस्तीफा दे देता...शिंदे सरकार पर आदित्य ठाकरे का करारा हमला

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार के लिए टाटा-एयरबस प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना सिर दर्द हो गया है। विपक्षी दल इसको लेकर शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर हैं। शिवसेना नेता (उद्धव गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया है।

उन्होंने कहा, सीएम शिंदे के विश्वासघात और महात्वाकांक्षाओं को लेकर राज्य पिछड़ने लगा है। एक रैली को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार के समय में केंद्र के साथ हमारी डबल इंजन सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।

महाराष्ट्र का निवेश दूसरे राज्यों में जा रहा

ठाकरे ने कहा, असंवैधानिक सरकार के सत्ता में आने के बाद एक इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। जो निवेश महाराष्ट्र में आना था वह दूसरे राज्यों में जा रहा है। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार थी तो सुभाष देसाई अपने कार्यकाल में 6.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश महाराष्ट्र में लाए थे।

मैं डिप्टी सीएम होता तो इस्तीफा दे देता

इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, गलत निर्णयों के चलते देवेंद्र फडणवीस की छवि दांव पर लग गई है। उन्होंने उद्योग मंत्री उदय सामंत के इस्तीफे की मांग की, साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार में अगर मैं डिप्टी सीएम होता तो अब तक पद से इस्तीफा दे दिया होता।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com